ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. NO.- 291-293**

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणवत्तापरक शोध

डॉ0 जेनुल आविदीन

एम0 कॉम0 एम0 एड0, पी0–एच0डी0– शिक्षाशास्त्र, मुरादाबाद (उ0प्र0), भारत

Received- 05.03.2022, Revised- 08.03.2022, Accepted - 12.03.2022 E-mail: aaryvart2013@gmail.com

सारांश: *– किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने एवं बनाए रखने में ज्ञान, सृजन, अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि इतिहास का अवलोकन करें तो यह पता चलता है कि समृद्ध सभ्यताओं – भारत, मेसोपोटासिया, चीन, मिस्र, ग्रीक से लेकर आधुनिक सभ्यताओं– अमेरिका, जर्मनी, इजरायल ऐसे अनेक देश हैं जिन्होंने बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के अनुसार योगदान दिया है। भारत आरंभ से ही ज्ञान का अनुसंधान का प्रमुख केन्द्र रहा है। 21वीं शदी ज्ञान की शदी है नालंदा तथा तक्षशिला के प्राचीन गौरव को पुनः स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। हमारा राष्ट्र पुनः ज्ञान शक्ति का उत्कृष्ट केन्द्र बने इसके लिए शिक्षा नीति के स्वरुप को समकालिक बनाने का प्रयास किया गया है। पूरी उच्च शिक्षा में एक मजबूत अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष निकाय के रुप में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन का सृजन किया जायेगा। इस शोध पत्र में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गुणवत्तापरक अनुसंधान से भारत विश्व में अपनी पहचान स्थापित करेगा, इस पक्ष पर प्रकाश डाला जायेगा।*

कुंजीभूत शब्द– अर्थव्यवस्था, ज्ञान, सृजन, अनुसंधान, अवलोकन, आधुनिक सभ्यताओं, भौतिक संपदा, समकालिक।

हमारा देश वर्ष 2030 तक युवा राष्ट्र के रुप में सर्वाधिक कामकाजी आबादी वाला देश होगा इसके लिए शत प्रतिशत साक्षरता अनिवार्य है। देश में युवाओं के जनसांख्यिकी अनुपात को जनसांख्यिकी लाभांश में बदलना है तो हमें अपने देश के बच्चों का भविष्य शिक्षा के माध्यम से सँवारना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, सशक्त भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को इस नीति के द्वारा ही साकार किया जा सकता है। जीवंत अर्थव्यवस्था को विकसित करने तथा बनाये रखने में ज्ञान, सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिससे समाज का उत्थान होता है और लगातार राष्ट्र को और भी अधिक ऊँचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा मिलती है। पूरे इतिहास का अवलोकन करें तो यह पता चलता है कि सबसे समृद्ध सभ्यताओं जैसे– भारत, मेसोपोटासिया, चीन, मिस्र और ग्रीक से लेकर आधुनिक सभ्यताओं– संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी, इजरायल तक ऐसे समाज थे और हैं जिन्होंने अपनी बौद्धिक और भौतिक संपदा को मुख्यतः नए ज्ञान के लिए प्रख्यात और आधारभूत योगदान द्वारा प्राप्त किया है जैसे– विज्ञान के साथ–साथ, कला, भाषा और संस्कृति के क्षेत्र में जिसने न केवल अपनी सभ्यताओं को बल्कि दुनिया भर की सभ्यताओं को परिष्कृत और उन्नत बनाया है। अनुसंधान एक महत्वपूर्ण पारिस्थिकीय तंत्र आज दुनिया में तेजी से होने वाले परिवर्तनों के साथ शायद पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है जैसे– जलवायु परिवर्तन, जैव प्रौद्योगिकी, एक डिजिटल बाजार का विस्तार में अपने विषाल प्रतिमान को फिर से एक प्रमुख ज्ञान समाज बनाने की क्षमताओं को सभी विषयों में उत्पादन के साथ एक महत्वपूर्ण विस्तार की आवश्यकता होगी। आज किसी भी राष्ट्र के आर्थिक, बौद्धिक, सामाजिक पर्यावरण और प्रौद्योगिकीय विकास के लिए शोध का महत्व पहले से अधिक है।

भारत में यदि भारत के अनुसंधान और नवाचार निवेश का अध्ययन किया जाए तो अमेरिका में 2.8 प्रतिशत, इजराइल में 4.3 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 4.2 प्रतिशत की तुलना में जी0डी0पी0 का केवल 0.69 प्रतिशत है। आज भारत को सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है जैसे कि अपने सभी नागरिकों को पीने की पानी की स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा, बेहतर परिवहन, गुणवत्तापरक वायु, बिजली और बुनियादी चीजों की पहुँच आदि है इसके लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तथा समाधानात्मक रवैये और क्रियान्वयन की जरुरत होगी जो न केवल शीर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर आधारित है बल्कि सामाजिक विज्ञान एवं मानविकी पर भी आधारित है। सामाजिक समस्याओं के हल निकालने के लिहाज से मूल्यवान होने के साथ–साथ किसी देश की पहचान उसकी प्रगति आध्यात्मिक और बौद्धिक संतुष्टि, इतिहास, भाषा, संस्कृति के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। भारत में शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान नवाचार और उनकी मात्रा बदलने में प्रयत्नशील है। वही विश्वविद्यालय सबसे सर्वश्रेष्ठ है जो शोध एवं अनुसंधान की प्रवृति का हो। भारत में विज्ञान, गणित, कला, साहित्य, स्वर विज्ञान भाषा से लेकर चिकित्सा और कृषि तक के विशयों में अनुसंधान एवं ज्ञान सृजन की एक लम्बी ऐतिहासिक परंपरा रही है। अब समय की माँग है कि जल्द से जल्द भारत प्रबुद्ध ज्ञान समाज के रुप में अपनी खोयी हुई स्थिति को शीघ्र प्रारंभ करे। 21वीं शदी में अनुसंधान एवं नवाचार का नेतृत्व करने के लिए तैयार रहें।

वर्तमान व्यवस्था में उच्च शिक्षा नीति कला, विज्ञान, शैक्षणिक, सहशैक्षणिक, अकादमिक सभी क्षेत्रों का विकास हुआ है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी इत्यादि बड़े एवं बहुविषयक विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं। नई शिक्षा नीति में उच्चतर षिक्षा संस्थानों को बड़े एवं विषयों वाले विश्वविद्यालयों कालेजों में रुपांतरित करना प्रस्तावित है जिसमें प्रत्येक में न्यूनतम 3000 विद्यार्थी हों, इस प्रकार उच्चतर शिक्षा के विखंडन को समाप्त करना है। 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा के विघटन को समाप्त करना है। 2040 तक सभी उच्चतर शिक्षा संसािनों को विविधता वाले संसािनों में रुपांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा सकल नामांकन अनुपात को 2035 तक वर्तमान के 26.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब विद्यार्थी गणित के साथ संगीत, भौतिक विज्ञान के साथ भूगोल इत्यादि विकल्पों का भी चयन कर सकेंगे। भारत में बेरोजगारी दर 6.6 फीसदी (सितम्बर 2020) है वहीं दूसरी ओर India Skill Report 2020 के अनुसार देश में मात्र 46.21 फीसदी युवा ही रोजगार परक क्षमताओं से युक्त हैं। मैनपावर टैलेंट सर्वे के अनुसार भारत में प्रतिभा कमी की दर 56 प्रतिषत है जबकि चीन 13 प्रतिशत, ब्रिटेन 19 प्रतिशत, अमेरिका 46 प्रतिशत, जर्मनी 51 प्रतिशत तथा जापान 89 प्रतिशत में दक्षता की कमी है। स्पष्ट है कि जैसा कौशल कंपनियों को चाहिए उपलब्ध नही है। व्यावसायिक शिक्षा को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा।

यह नीति भारत में अनुसंधान की गुणवत्ता और उसकी मात्रा को बदलने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को लागू करती है। नीति में स्कूली शिक्षा में निश्चित बदलाव शामिल है जैसे सीखने की खोज और खोज आधारित शैली, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक चिंतन पर बल शामिल है। छात्र हितों और प्रतिभाओं की पहचान के लिए विद्यालयों में कैरियर परामर्श उच्चतर शिक्षा का संस्थागत पुर्नगठन जो विश्वविद्यालयों में अनुसंधान को बढ़ावा दे, प्रशासनिक और विनियामक परिवर्तन जो शिक्षकों की और संस्थागत स्वायत्तता नवाचार को प्रोत्साहित करने वाले हो। यह नीति एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउण्डेशन की स्थापना को प्रात्साहित करती है जिससे राष्ट्र में गुणवत्तायुक्त अनुसंधान को सही रुप से विकसित और उत्प्रेरित किया जा सके। इसका प्रमुख लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा विशेष रुप से एन0आर0एफ0 योग्यता आधारित एवं पीयर रिव्यू पर आधारित शोध विधि का एक विष्वसनीय आधार प्रदान करेगा जो उत्कृष्ट शोध के लिए उपयुक्त प्रात्साहन के माध्यम से देश में अनुसंधान संस्कृति को विकसित करने में मदद करेगा। एन0 आर0 एफ0 प्रतिस्पर्धात्मक रुप से सभी बहुविषयकों में अनुसंधान को फंड देगा। सफल अनुसंधानों को मान्यता दी जायेगी। ऐसे संस्थान जो वर्तमान में किसी स्तर पर अनुसंधान को निधि प्रदान करते हैं जैसे–विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास, परमाणु ऊर्जा विभाग, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT), भारतीय कृषि अनुसंधान परिशद ;प्ब्।त्द्ध और विष्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के साथ–साथ विभिन्न निजी और परोपकारी संगठनों से वे अपनी प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुसार स्वतंत्र रुप से अनुसंधान जारी रखेंगे हलांकि नेशनल रिर्सच फाउण्डेशन सघन रुप से अन्य फंडिंग एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करेगा और विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य सक्षम अकादमियों के साथ काम करेगा इसके साथ ही इससे जुड़े अपेक्षित उद्देश्यों तथा प्रयासों में तालमेल की कमी को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। NRF की प्राथमिकता इस तरह होगी।

– सभी प्रकार के विषयों में प्रतिस्पर्धी तथा पीयर रिब्यू किये गए शोध प्रस्तावों के लिएफंड देना।
– शिक्षा संस्थानों में विशेषतः विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में जहाँ अभी अनुसंधान शैशवास्था में है इन संस्थानों को परामर्श प्रदान करके अनुसंधान शुरु करना विकसित करना और उसके लिए सुविधा देना।
– शोधार्थियों और सरकार की संबंधित शाखाओं तथा उद्योगों के बीच संपर्क बनाने एवं समन्वय का काम करना जिससे शोधार्थियों को लगातार अति तात्कालिक राष्ट्रीय अनुसंधान मुद्दों के बारे में बताया जा सके और जिससे ये नवीनतम सफलताओं के प्रति जागरुक रहे नीति निर्माता भी अनुसंधान के क्षेत्र। इससे इन सफलताओं को सर्वश्रेष्ठ तरीके से नीति और/अथवा उसके क्रियान्वयन में दर्ज किया जा सकेगा।
– उत्कृष्ट अनुसंधान और उनकी प्रगति को पहचानना।

उच्चतर शिक्षा की नियामक प्रणाली में यह सुनिश्चित करना होगा कि विनियमन, प्रत्यायन, फंडिंग और शैक्षणिक मानकों के निर्धारण जैसे विशेष कार्य, विशिष्ट, स्वतंत्र और सशक्त संस्थाओं, व्यवस्थाओं द्वारा संचालिक किये जायेंगे। इन चारो संस्थानों को भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HICI) के तहत 4 स्वतंत्र व्यवस्थाओं के रुप में स्थापित किया जायेगा। उच्चतर शिक्षा आयोग का पहला अंग राष्ट्रीय उच्चतर विनियामक परिशद (HNERC) होगा– यह उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए एक साझा और Single point regulation की तरह काम करेगा जिसमें शिक्षक शामिल है किन्तु चिकित्सकीय एवं विधिक शिक्षा शामिल है। इसका एक अंग उच्चतर षिक्षा अनुदान परिषद(HEGC) का गठन किया जायेगा जो पारदर्शी मानदंडों के आधार पर उच्चतर शिक्षा को फंडिंग तथा वित्तपोशण का कार्य करेगा जिसमें संस्थानों द्वारा विकसित आईडीपी और इनके क्रियान्वयन के जरिए प्राप्त की गयी उन्नति शामिल है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- I, Issues-23, YEAR- Jan.-March-2022

इस तरह इस नीति का उद्देश्य सभी वर्गों एवं श्रेणियों के विद्यार्थियों को समानतापूर्वक गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करेगी। स्कूली शिक्षा ही विश्वव्यापी उच्चशिक्षा का आधार होगी। इस शिक्षा नीति में रोजगारपूर्ण शिक्षा की बात की गयी है। शोध हेतु राश्ट्रीय शोध संस्थान बनाया जाएगा इस नीति का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्र निर्माण है इसका ढाँचा विश्वस्तरीय है परन्तु आत्मा भारतीय है। Study in India और Stay in India द्वारा विदेषी छात्रों को अपने यहाँ अध्ययन एवं शोध ा के लिए आकर्षित करना है। यह नीति अतीत के साथ आधुनिकता पर बल देती है। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी शिक्षा और श्रम की गरिमा पर ध्यान दिया गया है। तकनीकी आधारित ई कंटेंट बनाए जायेंगे, वर्चुवल लैब बनेगी। यह नीति शोध और शिक्षा के अंतर को खत्म करेगी। क्वालिटि एजूकेशन पर ज्यादा काम के बदले ज्यादा Autonomy दी जाय। ज्ञान में वृद्धि तथा गुणवत्ता तथा कौशल में वृद्धि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य है।

इस शिक्षा नीति में शोध संस्कृति को रतार देने के लिए हमें एक शोध इकोसिस्टम बनाना होगा, हर स्तर पर छात्रों को शोध से जोड़ना होगा। राष्ट्रीय शोध संस्थान नवाचार और बहुआयामी शोध को बढ़ावा दिया जाए। भारत में शोध फेलोशिप सर्वाधि क दिये जाने के बावजूद शोध का स्तर अच्छा नही है। राष्ट्रीय शोध संस्थान के माध्यम से सबको एक छतरी के नीचे एक रुप में देखकर एक नीति बनायी जायेगी। शिक्षकों को शोध का अधिकार मिलना चाहिए ताकि वे शोध के लिए आगे आए। शिक्षण संस्थान आपस में गठजोड़ करें। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षण तथा ई कन्टेन्ट पर बहुत जोर दिया है।

निष्कर्ष के रुप में हम यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुआयामी शिक्षा पर बल दिया गया है। बहुविषयक शिक्षा व रिसर्च को बढ़ावा मिलने से एक व्यावसायिक शिक्षा के वैकल्पिक पाठ्यक्रम के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सीखने का अवसर मिलेगा। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट को परिभाषित करने व स्वतंत्र अनुसंधान को बढ़ावा देना उच्च शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। नेशनल रिसर्च फाउण्डेशन की स्थापना से रिसर्च व नवाचार को प्रोत्साहित करने का इस दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है। नई शिक्षा नीति में शीर्ष 100 विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में अपने परिसर स्थापित करने से प्रतियोगिता व गुणवत्ता में वृद्धि हो जायेगी। छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के मानक निर्धारण निकाय के रुप में 'परख' नामक राष्ट्रीय आकलन केन्द्र की स्थापना करना 21वीं सदी के कौशल विकास अनुभव आधारित शिक्षण व तार्किक चिंतन को प्रोत्साहित करने एवं सैद्धान्तिक स्पष्टता के आकलन की प्राथमिकता पर ध्यान दिया गया। इस तरह से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उच्च गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है जैसे-जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन होगा उच्च शिक्षा को अधिक स्वायत्तता मिलती जायेगी। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक की महत्ता व गुणवत्ता को ध्यान रखा गया है साथ में शिक्षण प्रशिक्षण पर जोर दिया गया है। नयी शिक्षा नीति स्वीकार करती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए अभिप्रेरित शिक्षक आवश्यक है। इस शिक्षा नीति का एक प्रिय शब्द है ज्ञान युक्त समाज का निर्माण करना है। नई शिक्षा नीति गुणवत्ता, पहुँच, जबाबदेही, सामर्थ्य और समानता के आधार पर एक समूह प्रक्रिया के अंतर्गत है जहाँ विद्यार्थियों के कौशल विकास पर ध्यान दिया गया है वहीं पाठ्यक्रम को लचीला बनाया गया है ताकि विद्यार्थी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना कर सके। नई शिक्षा नीति अपनी पूर्ववर्ती नीतियों से इस मायने से भी विशेष है कि इसके अनेक प्रावधानों पर भारत सरकार पहले ही काफी काम कर चुकी है। 21वीं सदी भारत के समग्र उत्थान की शताब्दी होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति नें इसकी सुदृढ़ आधारशिला स्थापित कर दी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 http:/www Dristians.com
2. दैनिक जागरण-शोध संस्कृति को बढ़ाने वाली शिक्षा नीति, डॉ0 दिनेश शर्मा 19, सितम्बर 2020.
3. दैनिक जागरण-अच्छे अध्यापक तैयार करने की चुनौती 'संपादकीय' 5 सितम्बर 2020.
4. www.pmmodiyojna.in
5. www.navelnrattimesindiatime.com
6. http//www.ugc.ac.in/pdfnews/0144334.
7. http://www.mhrd.gov.in files-PDF national education policy2020.
8. youtube: http.youtube/l- 85cgc95x1.

*****